

दिनांक 30 मई, 1985

सं.ओ.वि./गुडगांवा/28-85/23268.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सो0एन0एक0प्रा10 लि10 चन्द्रतगर गुडगांवा के श्रमिक श्री राजा राम तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट वांछनीय समतंत्र हैं।

इस लिए, अब, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पहले हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त या उस से सुसंगत या उस से अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राजा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./करीदावाद/23275.—चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जो.0.जो.0. टैक्सटाइल 22 ए.0.एन.0. आई.0. दी.0. करीदावाद के श्रमिक श्री नेपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इससे इसके बाद लिखित मामले में कोई अद्योगिक विवाद है;

और चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-8-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उस से संबंधित मामला है:—

क्या श्री नेपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है।

सं.ओ.वि./फरीदाबाद/36-85/23282.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं फरीदाबाद कम्लैक्स, प्रशासन करोड़ाबाद के श्रमिक श्री चंचल बुमारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आद्योगिक विवाद है।

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवादको त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद की विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त या उस से सुसंगत या उससे संबंधित मामला है:—

ज्या श्रीमिति वंचल क्षमारा की सेवाओं का सम्पादन त्याथेचित्र तथा कीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत की हकड़ार है?

सं.ओ.वि./मिवानी/ 11-84/23289.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं 0 (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा चन्द्रगढ़ (2) हरियाणा राज्य परिवहन मिवानी के अधिक श्रेष्ठतावाल चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बोत्र इसमें इसके बाद लिखित सामले में कोई औद्योगिक विवाद है:—

और चंकि बृहियाणा के राज्यभाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछतीय समझते हैं।

इस लिए अब, श्रीबोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान का गँड़ शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिन्दू धर्म के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम./70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ निर्दिष्ट सरकारी अधिसूचना सं. 0 3664-1-ए.श्रम./70/1348 दिनांक, 8.5.1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतां को विवादग्रस्त या उसे लुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री सुभाष चन्द्र की सेवाओं का समाप्त न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?